महिलाओं ने बुलंद की शौचालय की मांग

भारत डोगरा

सुनीला देवी गर्भावस्था के अंतिम दिनों में थी और उसके लिए अधिक चलना कठिन हो रहा था। पर कानपुर की जिस गोस्वामी नगर स्लम बस्ती में वह रहती है वहां शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उसे शौच के लिए काफी दूर जाना ही पड़ता था। पहले जिन स्थानों पर महिलाएं बैठ सकती थीं वहां बैठने पर कुछ दिन पहले पुलिस के डंडे पड़े थे। कुछ पुरुषों को तो पुलिस पकड़ के भी ले गई थी। पास की कॉलोनी से कुछ व्यक्तियों ने पत्थर भी फेंके थे। अतः अब सुनीला देवी को पहले से कुछ और दूर चलकर जाना पड़ा।

अचानक उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। पास-पड़ोस की महिलाओं ने उसे देखा और संभाला। बहुत कठिनाई से उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सका व उसका जीवन बचाया जा सका।

इसी शहर की इंद्रा मलिन बस्ती में रहने वाले हरिलाल की त्रासदी तो इससे भी बुरी रही। उनकी बस्ती में एक ही सामुदायिक शौचालय है जो काफी समय से खराब पड़ा है। वृद्ध हरिलाल को भी अन्य स्लमवासियों की तरह एक अन्य सामुदायिक शौचालय की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन तबीयत खराब होने पर भी जब इतना चलना पड़ा तो वे रास्ते में ही गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई।

आज हरिलाल की बेटी आशा इस बस्ती में शौचालय की व्यवस्था सुधारने के लिए सक्रिय हो चुकी है। जो उसके पिता के साथ हुआ, वह किसी और के साथ न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उसने कई अन्य बस्तीवासियों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई। कई अधिकारियों को पत्र लिखे, आवेदन भेजे, फोन किए; अंत में अधिकारी नींद से जागे और उन्होंने इंद्रा मलिन बस्ती के सामुदायिक शौचालय को ठीक करवाने के लिए समुचित कार्रवाई की।

गोस्वामी नगर के लोग अभी इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। वे भी चाहते हैं कि जो सुनीला देवी को झेलना पड़ा वह किसी अन्य के साथ न हो। पर कई बार प्रयास करने पर भी अधिकारियों ने शौचालय स्थापित करने की उनकी बेहद ज़रूरी मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

यहां रहने वाली अनेक महिलाओं ने बताया कि शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें कितनी कठिनाई होती है व प्रतिदिन उन्हें कितनी अपमानजनक परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है।

इन कठिनाइयों को देखते हुए कानपुर की एक प्रमुख संस्था श्रमिक भारती ने वाटरएड के सहयोग से 150 बस्तियों में एक ऐसा प्रयास आरंभ किया है जिसके अंतर्गत शौचालयों व सफाई की मांग पर महिलाएं एकजुट हो रही हैं। प्रत्येक बस्ती में से पांच 'सिटिज़न लीडर' का चयन किया जाता है जिन्हें अपनी मांगों को असरदार ढंग से आगे बढ़ाने के अलावा सफाई के कार्यों सम्बंधी एकजुट प्रयास करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस परियोजना के सदस्य व सिटिज़न लीडर सम्बंधित अधिकारियों व वन विभाग से बेहतर संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह सुलभ इंटरनेशनल जैसे जिन निजी संस्थानों ने सामुदायिक शौचालय बनाए हैं, उनसे भी नज़दीकी संपर्क बनाया जाता है।

एक बार शौचालयों की मांग मान ली जाएं तो इनके रखरखाव के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रयास किया जाता है। निजी शौचालय बनाने के लिए भी बस्तीवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो निजी शौचालयों के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है मगर शहरी क्षेत्रों में नहीं है। अतः अधिक गरीब परिवार शौचालय नहीं बनवा सकते हैं। ऐसे में चार परिवारों को मिलकर 'शेयर टॉयलेट' बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 1000 रुपए की सहायता परियोजना की ओर से दी जाती है।

जिन स्कूलों में टॉयलेट का अभाव है वहां परियोजना की ओर से टॉयलेट बनवाने या मरम्मत हेतु सहायता भी दी जाती है; साथ ही विद्यार्थियों में सफाई के प्रति जागरूकता

बढ़ाने का अभियान चलाया जाता है। किशोरियों व महिलाओं में 'मेन्स्ट्रुएशन हाईजीन' फैलाने का विशेष प्रयास किया जाता है। जिन स्कूलों में अभी टॉयलेट नहीं हैं या खराब पड़े हैं, वहां के विद्यार्थियों व अध्यापकों ने बताया कि इस कारण उन्हें बहुत कठिनाई होती है व लड़कियों का तो स्कूल जाना ही कठिन हो जाता है।

आगे चलकर एक प्रयास यह होगा कि विभिन्न बस्तियों की सफाई सम्बंधी माईक्रो योजना बनाई जाए। इसमें नालियों, शौचालयों, कूड़े, स्नानघर सभी मुद्दों पर एक साथ विचार कर जन भागीदारी से योजना बनाई जाएगी। बस्ती स्तर की योजनाओं को उच्च स्तर पर नगर निगम, जल निगम आदि के अधिकारियों को सौंपा जाएगा व उनसे मांग की जाएगी कि शहर की व्यापक योजना बनाते समय इन बस्तियों की योजनाओं को भी इसमें समुचित स्थान दिया जाए।

उच्च अधिकारियों व सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं की इन उमड़ती भावनाओं व उनकी भागीदारी के आधार पर दिए गए सुधार के सुझावों पर समुचित ध्यान दें। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि संगठित होने के साथ-साथ अब ये महिलाएं उचित रख रखाव व सहयोग जैसी ज़िम्मेदारियां संभालने को तैयार हैं।

कुछ वर्ष पहले की एक घटना आज भी यहां प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। रजापुरवा बस्ती की कुछ महिलाएं अधिकारियों के पास सार्वजनिक शौचालय का एक प्रस्ताव लेकर गईं तो उच्चाधिकारियों ने यह कहकर टाल दिया कि पहले एक लाख रुपए स्वयं एकत्र करो तभी सरकार सहायता देगी। उन्होंने सोचा था कि इतने पैसे ये गरीब महिलाएं कहां से लाएंगी। पर इन गरीब महिलाओं ने ही घर-घर से चंदा एकत्र कर 55,000 रुपए इन अधिकारियों के सामने रख दिए तो वे हैरान भी हुए और शर्मिंदा भी। उन्होंने शेष 45,000 रुपए की राशि की छूट दे दी व आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा डाला जिससे बायोगैस भी बनती है। आज इस शौचालय से निकली गैस से स्लम बस्ती रोशन भी होती है व कई चूल्हे भी जलते हैं। यह एक प्रतीक है कि प्रयास करो तो बहुत कुछ हो सकता है।

समस्या केवल कानपुर की नहीं है, सैकड़ों शहरों की बस्तियों में महिलाओं की यही पीड़ा है। क्या सरकार इस ओर समुचित ध्यान देगी और स्लम बस्तियों की इस समस्या के समाधान की पहल करेगी? ***(स्रोत फीचर्स)***